भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 912

उत्तर देने की तारीख 04 फरवरी, 2026

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) 2.0

912.श्रीमती कमलेश जांगड़ेः

श्री तापिर गावः

श्री लुम्बाराम चौधरीः

श्री विजय बघेलः

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

श्री दिनेशभाई मकवाणाः

श्री पी. पी. चौधरीः

श्री दिलीप शइकीयाः

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः

श्री विजय कुमार दूबेः

डॉ. हेमंत विष्णु सवराः

श्री जी. सेल्वमः

श्री सी. एन. अन्नादुरईः

श्री प्रवीण पटेलः

डॉ. मन्ना लाल रावतः

श्री राजीव प्रताप रूडी:

श्री मनीष जायसवालः

श्रीमती स्मिता उदय वाघः

श्री भर्तृहरि महताबः

श्री गोडम नागेशः

श्री नव चरण माझीः

श्रीमती लवली आनंदः

श्री अभिमन्यु सेठीः
श्री जनार्दन मिश्राः
श्री नवसकनी के.:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) 2.0 के आरंभ से अब तक ऑप्टिकल फाइबर विस्तार, ग्राम पंचायतों और प्रमुख संस्थानों के ब्रॉडबैंड कवरेज के संबंध में विशेषकर तमिलनाडु, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रगति का क्या ब्यौरा है;

ख) राजस्थान राज्य में, विशेषकर पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के अंतर्गत शामिल की गई ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) तमिलनाडु, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश, राज्यों सहित विभिन्न राज्यों में विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार की पहुंच में क्षेत्रीय और ग्रामीण-शहरी असमानताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं:

(घ) विशेषकर तमिलनाडु, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश, राज्यों में अवसंरचना के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर मार्ग का अधिकार नियमावली (आरओडब्ल्यू), 2024 और केन्द्रीकृत आरओडब्ल्यू पोर्टल का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय भूमि मिशन 2.0 के अंतर्गत विशेषकर महाराष्ट्र और जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोई राज्य-वार अथवा जिला-वार मूल्यांकन किया गया है;

(च) विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ब्रॉडबैंड और मोबाइल अवसंरचना के विस्तार के अगले चरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार का भारतनेट परियोजना के अंतर्गत तमिलनाडु के सभी जिलों में सभी ग्राम पंचायतों को कब तक सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार करने का विचार है; और

(ज) महाराष्ट्र के पालघर जिले में ब्रॉडबैंड और मोबाइल अवसंरचना के विस्तार के लिए विगत 5 वर्षों के दौरान किए गए विस्तार और भावी योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क), (ख) और (ग) देश में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) के वर्ष 2019 में आरंभ होने के बाद से ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) की लंबाई 19.35 लाख रूट किमी से बढ़कर 42.53 लाख रूट किमी (31 दिसंबर, 2025 तक) हो गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग (डीओटी) टिकाऊ ब्रॉडबैंड/इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रहा है और ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में टेलीकॉम की पहुंच में असमानताओं को दूर कर रहा है और तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के ज़रिए डिजिटल डिवाइड को कम कर रहा है। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

i. भारतनेट प्रोजेक्ट ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को (मांग पर) ब्रॉडबैंड प्रदान करता है ।

ii. दूर-दराज के इलाकों, जैसे पूर्वात्तर, द्वीपसमूह, एलडब्ल्यूई (लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज़्म) से प्रभावित इलाकों, आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट/ब्रॉडबैंड और मोबाइल सर्विस (4जी सहित) के लिए कई स्कीम।

iii. चैन्नई तथा अंडमान और निकोबार के मध्य (2312 किमी) तथा कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच (1869 किमी) सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गईं, जिससे तेज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी मिली।

देश में भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत 31 दिसंबर 2025 को कुल 2,14,904 ग्राम पंचायत (जीपी) को सर्विस के लिए तैयार कर दिया गया है । राजस्थान के पाली लोकसभा क्षेत्र में, नियोजितन की गई 327 ग्राम पंचायतों में से 307 ग्राम पंचायतें को सर्विस के लिए तैयार कर दिया गया है। ब्लॉक हेडक्वार्टर (बीएचक्यू) को छोड़कर नियोजित की गई और सर्विस के लिए तैयार जीपी की राज्य-वार जानकारी अनुबंध-II में दी गई है। अब तक, देश भर में भारतनेट परियोजना के तहत 14,07,784 फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिसमें स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर (पीएचसी), आंगनवाड़ी सेंटर और पंचायत ऑफिस जैसे एंकर इंस्टीट्यूशन शामिल हैं।

4जी सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत (31 दिसंबर, 2025 तक) तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में कुल 4,917 गांवों की योजना बनाई गई थी, जिनमें से 4,584 गांवों को कवर किया जा चुका है। 4जी सैचुरेशन प्रोजेक्ट की स्थिति का ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

(घ) दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियम, 2024 (01 जनवरी, 2025 से प्रभावी) ने विभिन्न राज्यों और नगर पालिकाओं में मार्ग का अधिकार अनुमति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी समान मांग का अधिकार शुल्क सहित मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) ढांचे को मानकीकृत करके दूरसंचार बुनियादी ढांचे की तैनाती को और तेज कर दिया है , जिससे तेजी से अनुमोदन की सुविधा मिलती है और देश भर में दूरसंचार बुनियादी ढांचे की समय पर तैनाती सक्षम होती है।

केन्द्रीकृत आरओडब्ल्यू पोर्टल, 14 मई, 2022 को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर आरओडब्ल्यू एप्लीकेशन जमा करने के लिए प्रारंभ किया गया था। इससे पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित होती है, पेपरवर्क कम होता है और इस तरह आरओडब्ल्यू एप्लीकेशन में देरी और निपटान समय कम होता है। इससे तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ओएफसी बिछाने और टेलीकॉम टावर लगाने के लिए आरओडब्ल्यू अनुमति को आसान बनाने में मदद मिलती है। आरओडब्ल्यू पोर्टल को ज़्यादातर राज्यों में आरओडब्ल्यू नियम 2024 के अनुसार अपग्रेड किया गया है।

(ङ) जी, नहीं। हालाँकि, जलगाँव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, नियोजित सभी 653 ग्राम पंचायतों (जीपी) को भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के माध्यम से जोड़ा जा चुका है।

(च) एवं (छ) एनबीएम 2.0 के तहत विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के लिए निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :

i. 2.70 लाख गांवों में ऑपरेशनल ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) कनेक्टिविटी 95% अपटाइम के साथ

ii. 90% एंकर संस्थानों - स्कूल, पीएचसी, आंगनवाड़ी केंद्र और पंचायत कार्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।

इसके अलावा, दिनांक 04.08.2023 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट फेज़-I और फेज़-II के मौजूदा नेटवर्क के अपग्रेडेशन, शेष ग्राम पंचायतों में नेटवर्क तैयार करने, 10 साल तक ऑपरेशन और मैंटेनेंस और उपयोग के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंज़ूरी दी है। शेष बिना ग्राम पंचायत वाले गांवों को कनेक्टिविटी उनकी जीपी से मांग के आधार पर

देने का प्रस्ताव है, जिसमें अगले पांच सालों में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1.50 करोड़ एफटीटीएच कनेक्शन देने का लक्ष्य शामिल है, जिसमें स्कूल, पीएचसी, आंगनवाड़ी सेंटर, पंचायत ऑफिस इत्यादि जैसे सरकारी संस्थानों को कवर करने की प्राथमिकता दी गई है।

मोबाइल सर्विस के लिए अन्य स्कीम के साथ 4जी मोबाइल सर्विस को सैचुरेट करने का प्रोजेक्ट भी कार्यान्वित हो रहा है। यह परियोजना/स्कीम देश के उन इलाकों जैसे ग्रामीण, दूर-दराज, दुर्गम, सीमावर्ती गांवों और अन्य प्राथमिकता वाले इलाकों में मोबाइल सर्विस देने के लिए हैं जहां अभी तक मोबाइल सेवाएं नहीं पहुंची हैं,

31 दिसंबर, 2025 तक, सरकार द्वारा वित्तपोषित विभिन्न मोबाइल परियोजनाओं के तहत देश के दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों में 23,694 मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं।

महाराष्ट्र के पालघर जिले में, भारतनेट परियोजना के तहत, 31 दिसंबर, 2025 तक, नियोजित की गई 474 जीपी में से 461 जीपी को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा, पिछले पांच सालों में 4,336 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) लगाए गए हैं। वर्ष-वार विवरण अनुबंध-IV में दिया गया है।

(ज) तमिलनाडु में भारतनेट को राज्य आधारित मॉडल के ज़रिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

*****

अनुबंध-।

दिनांक 04.02.2026 उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 912 के भाग (क), (ख) और (ग) में संदर्भित अनुलग्नक।

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	ओएफसी बिछाई गई (2019 तक) रूट किमी में	ओएफसी बिछाई गई (31 दिसंबर, 2025 तक) रूट किमी में
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	806	1544
2	आंध्र प्रदेश	90335	251753
3	अरुणाचल प्रदेश	5247	9913
4	असम	38789	93234
5	बिहार	76525	129992
6	चंडीगढ़ (यूटी)	2055	24763
7	छत्तीसगढ	55138	118793
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (यूटी)	329	1328
9	दिल्ली (केंद्र शासित प्रदेश)	37632	77409
10	गोवा	3366	5065
11	गुजरात	115169	290429
12	हरियाणा	55853	83932
13	हिमाचल प्रदेश	21769	35787
14	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	19624	44479
15	झारखंड	37151	82034
16	कर्नाटक	127418	226763
17	केरल	56490	259252
18	लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश)	3110	5663
19	लक्षद्वीप (यूटी)	34	59
20	मध्य प्रदेश	151207	263453
21	महाराष्ट्र	198145	406637
22	मणिपुर	5080	10499
23	मेघालय	3827	11952
24	मिजोरम	3016	8332

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	ओएफसी बिछाई गई (2019 तक) रूट किमी में	ओएफसी बिछाई गई (31 दिसंबर, 2025 तक) रूट किमी में
25	नगालैंड	5042	10057
26	ओडिशा	71865	156298
27	पुडुचेरी (यूटी)	-	138
28	पंजाब	68755	197105
29	राजस्थान	138865	239458
30	सिक्किम	3035	4827
31	तमिलनाडु	121462	308907
32	तेलंगाना	62032	237946
33	त्रिपुरा	6272	11294
34	उत्तर प्रदेश	232732	406697
35	उत्तराखंड	27855	50178
36	पश्चिम बंगाल	89872	187364
	कुल	**1935903**	**4253337**

अनुबंध- II

दिनांक 04.02.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 912 के भाग (क), (ख) और (ग) में संदर्भित अनुलग्नक।

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**कुल प्लान किए गए जीपी (बीएचक्यू को छोड़कर)**	**टोटल सर्विस रेडी (बीएचक्यू को छोड़कर)**
1	असम	2665	1507
2	बिहार	8405	8340
3	छत्तीसगढ	11711	9695
4	हरियाणा	6256	6082
5	जम्मू और कश्मीर	4299	1101
6	कर्नाटक	6090	6084
7	केरल	978	978
8	मध्य प्रदेश	22858	17850
9	महाराष्ट्र	27939	24575
10	पंजाब	13337	12668
11	राजस्थान	11352	8776
12	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	43072	34274
13	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	16218	12472
14	उत्तराखंड	7937	1993
15	पश्चिम बंगाल	3340	2677
16	सिक्किम	185	35
17	चंडीगढ़	12	12
18	लक्षद्वीप	10	9
19	अरुणाचल प्रदेश	1959	1124
20	नगालैंड	1007	236
21	मणिपुर	2936	1475
22	मिजोरम	784	540
23	त्रिपुरा	1179	740
24	मेघालय	1857	698
25	गुजरात	14324	14320
26	दमन और दीव	18	18

27	दादरा और नगर हवेली	20	20
28	पुदुचेरी	110	98
29	आंध्र प्रदेश	13481	12955
30	तेलंगाना	12865	10833
31	ओडिशा	6798	6785
32	झारखंड	4416	4390
33	हिमाचल प्रदेश	3615	410
34	लद्दाख	193	193
35	गोवा	191	0
36	तमिलनाडु	12525	10869
37	अंडमान और निकोबार	72	72
	कुल	**265014**	**214904**

अनुबंध- III

दिनांक 04.02.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 912 के भाग (क), (ख) और (ग) में संदर्भित अनुलग्नक।

4जी सैचुरेशन प्रोजेक्ट की स्थिति (31 दिसंबर, 2025 तक)									
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**टावर की योजना**			**गाँव की योजना**	**हवा में**			**कवर किया गया गांव**
		नया	**उन्नत करना**	**कुल**		**नया**	**उन्नत करना**	**कुल**	
1	आंध्र प्रदेश	1339	7	1346	2953	1236	7	1243	2759
2	राजस्थान	1341	17	1358	1656	1242	17	1259	1528
3	तमिलनाडु	222	35	257	308	220	35	255	297
	कुल	**2902**	**59**	**2961**	**4917**	**2698**	**59**	**2757**	**4584**

अनुबंध- IV

दिनांक 04.02.2026 उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 912 के भाग (ज) में संदर्भित अनुलग्नक।

पालघर जिले में स्थापित बीटीएस की संख्या					
वर्ष	**2जी**	**3जी**	**4 जी**	**5जी**	**कुल बीटीएस**
2021	79	1	670	0	750
2022	71	0	438	152	661
2023	81	0	289	1099	1469
2024	113	0	345	154	612
2025	208	1	466	169	844
कुल	**552**	**2**	**2208**	**1574**	**4336**